



पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के बाद सोमवार को जयपुर लौट आये। पायलट की हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव के संबंध में गहन चर्चा हुई। पायलट 20 सितम्बर से ही पुनः अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में आयोजित कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे।

सचिन पायलट ऐतिहासिक सी.डब्ल्यू.सी. बैठक के बाद लौटे राजस्थान

वापसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने सचिन पायलट का शानदार स्वागत किया

- सचिन पायलट को तेलंगाना में कांग्रेस के प्रचार की कमान सौंपी गई।
- दो दिवसीय बैठक में पायलट ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व के.सी. वेणुगोपाल व अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की।
- हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी संगठन ने पायलट का स्वागत किया।

जयपुर, 18 सितम्बर। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था, सी.डब्ल्यू.सी. की हैदराबाद में हुई 2 दिवसीय बैठक के बाद सचिन पायलट मंगलवार शाम को राजस्थान वापस लौट आए हैं। इस दौरान सचिन पायलट को आगामी तेलंगाना चुनाव के लिए पार्टी के हाई कमान द्वारा प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। सोमवार को सचिन पायलट ने नामपल्ली विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए जन संपर्क तथा प्रचार भी किया।

2 दिवसीय बैठक के दौरान सचिन पायलट की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी,

खड़गे और राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आयेंगे

दोनों नेता कांग्रेस के नये बनने वाले प्रदेश मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे

- कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय, शिप्रा पथ पर सिटी पार्क के सामने बनेगा। कार्यालय के लिए 6000 वर्ग गज जमीन आवंटित की गई है।
 - राहुल व खड़गे कांग्रेस के विभिन्न स्तर के 55 हजार पदाधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे।
- जयपुर, 18 सितम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आयेंगे और राजस्थान कांग्रेस के नए मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे।
- मुख्यालय के शिलान्यास के बाद राजस्थान कांग्रेस की सभा के साथ कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए राजस्थान कांग्रेस अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेगी। इस सभा के जरिए कांग्रेस के बृथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को चुनावी टास्क दिए जाएंगे।
- राजस्थान कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए 55 हजार पदाधिकारियों को बुलाया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के 52 हजार बृथ अध्यक्षों, 2200 मंडल अध्यक्षों, 400 ब्लॉक अध्यक्षों, 40 जिलाध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को इस सभा में बुलाया गया है। कार्यक्रम की तैयारी देखने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

इस वर्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और प्रतिभूति लेन-देन कर सहित व्यक्तिसगत आयकर (पी.आई.टी.) 447291 करोड़ रुपये रहा है। इस अवधि में प्रत्यक्ष कर का सकल संग्रह 9,87,061 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 8,34,469 करोड़ रुपये की तुलना में 18.29 प्रतिशत अधिक है।

कांग्रेस का चतुर दांव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इतिहास का उल्लेख किया तथा कांग्रेस शासन के दौरान लाई गई उन 20 प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लाये गये सभी प्रमुख कानूनों के उल्लेख के साथ ही, दासता-उन्मूलन का उल्लेख किया। खड़गे ने कहा, “नेहरू जी का मानना था कि मजबूत विपक्ष की गौरमीजुदगी का अर्थ है कि, सिस्टम में उल्लेखनीय कमियाँ एवं खामियाँ हैं। अगर सशक्त विपक्ष नहीं है, तो यह अच्छी बात नहीं है। अब, जब सशक्त विपक्ष है तो इसे ई.डी., सी.बी.आई. -- के जरिये कमजोर करने पर फोकस किया जा रहा है।” जवाहर लाल नेहरू तथा राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुये, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “नेहरू जी ने बड़े

मुश्किल समय में भारत का नेतृत्व किया। वे भारत की आजादी की खातिर 14 वर्ष जेल में रहे। नये संसद भवन में पहुँच जाने मात्र से, कुछ नया नहीं हो जायेगा।” उन्होंने कहा, भाजपा को उनके (नेहरू) बारे में अपमानजनक बातें करना बंद कर देना चाहिए।

खड़गे ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में केवल दो बार बयान दिये हैं तथा उन्होंने इसकी (जवाब देने की) तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह से की है। उन्होंने कहा, “अपने कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 बार तथा मनमोहन सिंह ने 30 बार बयान दिये थे।” उन्होंने आगे कहा, “किन्तु प्रधानमंत्री मोदी ने चन्द् “प्रथागत एवं औपचारिक टिप्पणियों” के अलावा केवल दो बार ही बयान दिये हैं।”

प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल एवं पार्टी के अन्य शीर्ष नेतृत्व के सदस्यों से हुई। इन बैठकों में आगामी राजस्थान चुनाव और लोक सभा चुनाव से संबंधित एहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

हैदराबाद यात्रा के दौरान, पायलट को वहां पर स्थित, प्रवासी राजस्थान संगठन, ने भी सम्मानित किया और उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

सचिन पायलट 20 सितंबर को अपनी विधान सभा क्षेत्र, टोंक में आयोजित कार्यक्रमों में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।

झारखण्ड के मु.मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने कथित अवैध खनन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के समन को चुनौती देने वाली झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सोमवार को खारिज करते हुए उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय दरवाजा खटखटाने को कहा।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि वो राहत के लिए पहले उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करें।

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बोस ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, आप (सोरेन) उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? पहले आप वहां जाएं।

‘प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक शख्स संसद तक पहुंच गया’

- नई दिल्ली, 18 सितम्बर। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, आज यह पुराने भवन में आखिरी दिन है। कल से हम नए संसद भवन में शिफ्ट होंगे और नई शुरुआत होगी। लेकिन यह भवन हमारे लिए साड़ी विरासत रहा है और तमाम प्रेरक पल यहां से जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भावुक भी नजर आए और कहा कि इसी संसद भवन से हमारी तमाम यादें भी जुड़ी हैं, जो झकझोर देती हैं। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का भी इस दौरान जिक्र किया और कहा कि प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक शख्स संसद तक पहुंच गया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को विरोध

मोदी मंत्रिमण्डल ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया

संसद सत्र में विधेयक सदन में पेश किया जायेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा

- नई दिल्ली, 18 सितम्बर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार को केंद्र की कैबिनेट बैठक हुई। संसद के एनेक्सी भवन में हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। इस बैठक के दौरान महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से पास हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की। अपने ट्वीट में प्रहलाद पटेल ने लिखा कि महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया।
- केंद्र सरकार ने सोमवार शाम तक संसद सत्र का एजेण्डा गुप्त रखा था, शुरू से ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि, प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे देश की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन हो जायेगा।
- केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में पुष्टि की। अपने ट्वीट में प्रहलाद पटेल ने लिखा कि, महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया।

हैं। रमेश ने कहा कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पदों के पीछे की राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।

जयराम रमेश ने अपने एक पुराने पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक की पृष्ठभूमि का हवाला दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। रमेश के अनुसार, अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्ह राव ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया था। दोनों विधेयक

- चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले विधेयक को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव वाला बिल इसी सेशन में पेश करेगी। इसके तहत आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के दर्जे की बजाय कैबिनेट सचिव वाली हैसियत दी जानी थी। इसका तीखा विरोध हो रहा था। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की स्वायत्ता से समझौता बता रहा था। को वही 9 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पी.एम. मोदी को बिल की लिखा था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अब सरकार खुद अपने स्तर पर भी बदलाव

‘प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक शख्स संसद तक पहुंच गया’

- प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला गरीब करने वाला संसद पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा। उन्होंने कहा कि इस भवन को बनाने का फैसला भले ही अंग्रेजी हुकूमत का था, लेकिन इसके निर्माण में परिश्रम और पैसा देश के लोगों का ही लगा था।
- इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने हमें कई यादें दी हैं। भले ही हम नए भवन में जा रहे हैं, लेकिन यह भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। पुराने भवन की यादों को लेकर पी.एम. मोदी ने कहा कि इस सदन से विदाई लेना भावुक पल है।

‘भाजपा सनातन धर्म का मुद्दा मूल मसलों... अडानी केस में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसमें वर्तमान समिति के कुछ सदस्यों के हितों के टकराव पर चिंता व्यक्त की गई है। मार्च 2023 में शीर्ष कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच और नियमन की संभावित असफलताओं की जांच के लिए समिति गठित की थी। समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस (रिटायर्ड) अभय मनोहर सप्रे और सदस्यों में शामिल हैं ओ.पी. भट्ट, जस्टिस पी. देवघर, के.वी. कामथ, नंदन नीलकेणिंग और सोमसुंदर सुंदरेशना। आवेदन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ओ.पी. भट्ट को शामिल करने पर ऐतराज उठाया गया है, जो वर्तमान में अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनो के अध्यक्ष हैं। इसमें कहा गया है

सकती है। वहीं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना कि वन नेशन, वन इलेक्शन पर बात होने की उम्मीद है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर जोर दिया जा रहा था। इसलिए सबसे ज्यादा अनुमान इसी को लेकर था। सोमवार को संसद के विशेष सत्र के संबोधन के दौरान भी पी.एम. मोदी ने इस बारे में संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि संसदीय इतिहास के प्रारंभ से अब तक दोनों सदनो में कुल मिलाकर लगभग 7500 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया है जिनमें करीब 600 महिला सदस्य रही हैं। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे महिला सदस्यों की संख्या बढ़ती गयी है। माना जा रहा था कि यह महिला आरक्षण का संकेत है।

पहली बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाषण में उन्होंने कहा, नेहरू के “ट्रिस्ट विद डैस्टिनी” भाषण की गुंज भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

नेहरू ने, 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि, “आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता में आँखें खोलेंगा।”

मोदी ने कहा, “आज भारत की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा को याद करने का अवसर है। हम भले ही नई इमारत में शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन यह भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि यह भारतीय प्रजातंत्र की यात्रा का “स्वर्णिम अध्याय” है।

जे.डी.एस. सांसद को राहत

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रहलान रेव्ना की संसद सदस्यता रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. परिदारवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के एक सितंबर के आदेश पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

केरल और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपरिस्थिति नामभारत की है। लेकिन बड़ा खतरा यह है कि, इससे गठबंधन के अन्य घटकदल बड़ी संदेबाजी करने के लिये तथा अपनी क्षमता से बहुतकर दावेदारी करने के लिये प्रेरित - प्रोत्साहित हो सकते हैं। अरविन्द केजरीवाल की “आप” तथा कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में सीट-शेयरिंग के मामले में पहले से ही परस्पर उलझ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी तथा पंजाब में कांग्रेस की राज्य इकाइयों के नेता पार्टी नेतृत्व की सीट-शेयरिंग व्यवस्था की अवहेलना करने सलाह दे रहे हैं। साफ जाहिर है कि, इस प्रकार की घटनाओं से भाजपा को पूरा मौका मिल जायेगा, नवगठित विपक्षी गठबंधन में एकता के अभाव की आलोचना करने का। लेकिन, जैसा कि इंडिया गठबंधन के नेता घोषणा कर चुके हैं, वे, जहाँ तक संभव होगा, वन-टु-वन की लड़ाई ही रखना चाहेंगे।

सूत्रों ने कहा कि, उन राज्यों में, जहाँ कांग्रेस, भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, सहमति /समझौते तक पहुँचने की कोशिश की जायेगी। इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा तथा हिमालचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।